(c) whether the C.B.S.E. has already taken some long-terms measures to stop malpractices in the examinations;

(d) if so, what are the details thereof;

(e) whether the C.B.S.E. also propose to ensure that centres of examinations for students, particularly of girls are within a radius of half kilometre in view of increasing incidents of eve-teasing in D.T.C. buses; and

(f) if not what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (d) Yes, Sir. The Central Board of Secondary Education (CBSE) conducts its examinations in accordance with its Examination Bye-Laws which have laid down rules to deal with cases involving unfair means. However, the CBSE has further decided to take both short term and long term measures to control malpractices in Examinations.

Among the short term measures, the most important is the use of multiple sets of question papers based on the same blue print. The multiple sets of question papers are being introduced in Delhi w.e.f. 1992 Examinations.

As part of the long term measures, the Board is going ahead with the trial of an alternative Model of Examination in which the power to rank order the students will be given to the schools while power to scale the marks of the students will be retained by the Board.

(e) and (f) Yes, Sir; as far as administratively possible.

Deficient curriculum..

857. DR. YELAMANCHILI SIVAJI:
SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the school bags of students have become imbalanced due to deficient curriculum and the resultant increase in the number of books; and

(b) what steps Government are contemplating to remedy the situation?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) One of the factors that has contributed to the overburdening of students is the tendency on the part of the schools to recommend a large number of books to the students. This tendency was sought to be curbed by issuing instructions from the Ministry of Human Resource Development in October, 1989 and September, 1991 to the Education Secretaries of all States and Union Territories to ask the schools not to prescribe more books than which are actually required and to ensure that children carry only those textbooks/exercise books which are actually required on a particular day.

! The whole question of curriculum load is a complex question and there are no simple solutions. It has to be tackled in a comprehensive way and would include curriculum reform, examination reform, better pedagogical practices and teacher training. All these aspects have been emphasised by the NCERT from time to time.

A major exercise is being initiated in consultation with parents, teachers, experts etc. to reduce the burden of academics on children.

केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

858. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आलिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के बहुत से पद रिक्त पड़े हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले दो सत्रों के दौरान इन रिक्त पदों को भरने के लिये अभी तक कोई भर्ती नहीं की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया कब तक शुरू होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) उन पदों की संख्या जिस पर सत्र के आरम्भ में नियमित अध्यापकों को तैनात नहीं किया जा सका, निम्नलिखित है:-

पी०जी०टी०	1047
टी०जी०टी०	870
पी०आर०टी०	801
विविध वर्गों के अध्यापक	873

(ग) से (ङ) नामों के विद्यमान पैनल क्योंकि उपयोगिता की प्रक्रिया में है, अतः कोई नयी नियुक्ति नहीं की गयी थी ।

केन्द्रीय विद्यालयों में योग अध्यापक

859. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन में योग अध्यापकों के कार्य की नियमित सावधिक पुनरीक्षा के लिये कोई कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) योग शिक्षण की योजना आरंभ में प्रयोगात्मक आधार पर एक वर्ष के लिए वर्ष 1981 में केन्द्रीय विद्यालयों में शुरू की गई थी । यह लगातार समीक्षाधीन रही है । प्रथम समीक्षा भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज हैदराबाद द्वारा वर्ष 1982-83 में की गई थी जिसने सिफारिश की थी कि प्रयोग की स्थिति में योग शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन अपेक्षाकृत कठोरतापूर्वक किया जाना चाहिए और संभव हो तो यह कार्य शैक्षिक वर्ष 1983-84 के अंतिम दिनों में किया जाए ।

तदनुसार, वर्ष 1983-84 के अंतिम दिनों में डा० पी० डी० शुक्ल की अध्यक्षता में एक समिति ने इस योजना का मूल्यांकन किया तथा जून, 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस समिति की रिपोर्ट की जांच मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जनवरी, 1986 में की गई तथा योजना को पुनः प्रयोगात्मक आधार पर शैक्षिक वर्ष 1986-87 के अन्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने 26 सितम्बर, 1986 को संपन्न हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये :—

(i) योग को केन्द्रीय विद्यालयों के शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के साथ समेकित कर दिया जाना चाहिए ।

(ii) योग को 1 से 5 कक्षाओं तक नहीं पढ़ाया जाना चाहिए ।

(iii) मौजदा योग शिक्षकों को तीन वर्षों की अवधि में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक तथा व्यावसायिक अर्हताओं को प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए ।